में बोल सकते हैं जिसके लिए कि संयुक्त राष्ट्र संगठन में दुभाषिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि प्रतिनिधिमंडल का कोई सदस्य हिन्दी में बोलना चाहे तो वह अनुवाद/भाषांतर की व्यवस्था करके ऐसा कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के दौरान इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जब कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में माननीय संसद सदस्य और जाने-माने गैर सरकारी व्यक्ति सदस्य की हैसियत से वहीं रहते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संगठन में नई भाषा शुरू करने का खर्च उस सदस्य (देशों) पर पड़ता है जो उस भाषा का प्रस्ताव करता है और इस प्रकार की भाषा को शुरु करने पर अतिशय खर्च होगा।

विदेश मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक

253. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा विभाग ने विदेश मंत्रालय, इसके दूतावासों और अन्य कार्यालयों को अपने अधिनियम तथा वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन से छूट दी है, यदि नहीं, तो अब तक मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की केवल एक ही बैठक किए जाने तथा विदेशों में भारतीय दूतावासों में हिन्दी से संबंधित कोई कार्यक्रम लागू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय दूतावासों के पुस्तकालयों में हिन्दी की पुस्तकें तथा पत्रिकायें बहुत कम हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय संस्कृति को विदेशों में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायनन्) : (क) जी, नहीं। विदेश मंत्रालय और इसके कार्यालय राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के विभिन्न प्रावधानों का अनुसरण करते हैं तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी हिन्दी के प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

इस मंत्रालय में हाल ही में केन्द्रीय हिन्दी समिति की उप समिति के स्थान पर हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया था। इसकी बैठक 14-2-86 को हुई थी। दूसरी बैठक जून में होनी थी किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण यह बैठक नहीं बुलाई जा सकी। समिति की बैठक अब 22-8-86 को होगी।

विदेश स्थित हमारे राजदूतावास राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियमों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने की यथासंभव कोशिश करते हैं। तथापि, उनके कार्य का स्वरूप काफी भिन्न होता है क्योंकि उनके कार्य का अधिकांश भाग विदेशी सरकारों तथा विदेशियों से संबंधित होता है जिनकी भाषा हिन्दी नहीं है।

(ख) और (ग) यह सही नहीं है कि भारतीय राजदूतावासों के पुस्तकालयों में हिन्दी की बहुत कम पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं। मंत्रालय पिछले कुछ वर्षों से विदेश स्थित अपने मिशनों को नियमित रूप से हिन्दी की पुस्तकें भेज रहा है जिनमें भारतीय साहित्य, संस्कृति तथा धर्म से संबंधित विषयों की पुस्तकें भी शामिल होती हैं। मिशन उन विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों/वैयक्तिकों को भी हिन्दी पुस्तकें, फिल्में, रिकार्ड तथा अन्य सामग्री भेंट करते हैं जो भारतीय संस्कृति में रूचि रखते हैं। हमारे मिशन विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन भी करते हैं और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों पर 'भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित समारोहों में भी भाग लेते हैं। इन समारोहों में विदेशियों की उपस्थिति का भी स्वागत किया जाता है।

वित्त मंत्रालय के कार्यालयों में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

254. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों, विशेषकर बैंकों